प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छत्तीस' [28/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 3441]

परिशिष्ट–1

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 3441

(1) एशियाई सिंहो के पुर्नस्थापना हेतु "जीरो एक्शन प्लान" नवीनतम IUCN गाइडलाइन्स (2013) के अनुरूप डॉ. वाई. वी. झाला (WII देहरादून) एवं डॉ. रवि चैलम द्वारा 06 सप्ताह के भीतर तैयार किया जाये। (29.07.2013)

(2) कूनो पालपुर में पुर्नस्थापित होने वाले सिंहो की आबादी (Translocated population) फ्री रेंजिंग तथा आत्मनिर्भर होनी चाहिये। (29.07.2013)

(3) सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों एवं पुनर्स्थापना के उद्देश्य हेतु आवश्यक अध्ययनों (वैज्ञानिक एवं सामाजिक दोनों) का समावेश करने हेतु डॉ0 रवि चेल्लम एवं डॉ0 वाई0 झाला, एक्शन प्लान को संशोधित करेंगे। IUCN गाइड लाइन्स का समावेश भी एक्शन प्लान में करेंगे। (28.04.2014)

(4) सिंहो की पुर्नस्थापना हेतु जीरो एक्शन प्लान में से निकालकर एक विशिष्ट रोडमेंप बनाई जायें जिसमें पुर्नस्थापना की समय सीमा के साथ किये जाने वाले सभी संम्भव कार्यो का समावेश हो।(28.04.2014)

(5) कूनो पालपुर के क्षेत्रफल विस्तार के संबन्ध में किये गये प्रयास को म0प्र0 सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय को सूचित करेगा तथा Annual plan of operation (APO) के अंतर्गत सिंहो के पुर्नस्थापना हेतु पर्यावरण वन मंत्रालय से बजट की मांग करेगा। म0प्र0 सरकार सिंहो के पुर्नस्थापना हेतु की जाने वाली प्राथमिक गतिविधियों हेतु राशि विमुक्त करने हेतु प्रस्ताव पर्यावरण वन मंत्रालय भेजेगी। (28.04.2014)

(6) पुर्नस्थापना से संबन्धित वैज्ञानिक शोध (Scientific studies) IUCN गाइड लाइन के अनुसार WII देहरादून द्वारा की जायेगी। पुर्नस्थापना से संबन्धित उचित सामाजिक शोध (Social studies) IUCN गाइड लाइन के अनुसार करने हेतु संस्थान/विश्वविद्यालय को चिन्हित करने का कार्य भी WII द्वारा किया जायेगा। एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लिये गये एक्शन पर एक अंतरिम रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सोंपी जायेगी। (28.04.2014)

(7) जीरो एक्शन प्लान का अंतिम ड्राफ्ट सभी सदस्यो द्वारा दिये गये सुझावों एवं प्रतिकियाओं का समावेश करते हुये 23 मार्च 2015 तक कमेटी (पर्यावरण वन मंत्रालय) को सौंपा जायेगा। (11.02.2015)

(8) कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि एक बार वर्तमान दरों पर विशिष्ट टाइम लाइन्स के साथ मान्य योग्य प्लान प्राप्त होने पर केन्द्रीय मंत्रालय इस परियोजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु विभिन्न विकल्पों का पता लगायेगी।

(9) सिंहो को कूनो पालपुर अभ्यारण्य में पुर्नस्थापित करने के लिये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाये तथा म0प्र0 सरकार पुर्नस्थापना हेतु IUCN गाइड लाइन के अतंर्गत सिंहो की आनुवांशिक स्थिरता बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक वैज्ञानिक उपाय करेगी। (13.05.2016)

(10) जीरो एक्शन प्लान को कियान्वित करने से पहले कूनो पालपुर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना चाहिए जिससे पुर्नस्थापना संबंधी सभी गतिविधियों का प्रभावी रूप से कियान्वयन हो सके। (13.05.2016)

(11) भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पुनर्स्थापना को प्रभावी बनाने हेतु, विस्तृत कृत्यों, जिम्मेदारियों एवं कार्य बिन्दुओं का निर्धारण करते हुये दिनांक 30.05.2016 तक एक एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जावेगा। प्रत्येक पार्टी (गुजरात सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं (MoEFCC) के किरदार, अधिकार, जोखिम एवं विशेषाधिकारों को स्पष्ट करते हुये आगामी बैठक में एक त्रिदलीय (Tripartite) अनुबंध का ज्ञापन बनाया जाकर अनुमोदित किया जावेगा। (13.05.2016)

(12) कमेटी द्वारा, WII देहरादून द्वारा पुर्नस्थापना से संबंधी की जाने वाली वैज्ञानिक तथा सामाजिक शोध से संबंधित प्रस्तावो को अनुमोदित किया गया। यह शोध 03 वर्ष के लिये होगा तथा प्रथम वर्ष के लिये बजट 2.42 करोड़ रु. रहेगा जिसे WII अपने बजट में शामिल करेगा। (13.05.2016)

(13) दो राज्य विशिष्ट समन्वय समिति (गुजरात एवं म0प्र0) बनाई जायेगी जो अपने–अपने राज्यों की पुर्नस्थापना संबंधी सभी मुद्दों पर कार्य करेगी इसके अतिरिक्त, निदेशक – Wildlife preservation, MoEFCC की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया जायेगा। जो कि, उपरोक्त दोनों समिति को सुपरवाइज करेगी। (13.05.2016)

15/7/16

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन [illegible]-2

परिशिष्ट–2

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 3441

(1) कूनो वन्यप्राणी अभ्यारण्य से 24 ग्रामों को विस्थापित किया गया है। विस्थापित किये गये ग्रामों के परिवारों की संख्या 1543 है।

(2) विस्थापित हुये ग्रामों की रिक्त भूमि पर घास के मैदानों का विकास किया जा रहा है। इस हेतु बहुवार्षिक एवं खाद्य घास की स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है।

(3) वन्यप्राणियों हेतु वर्ष भर पीने हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु 06 तालाब ग्रेविटी पाइप लाइन से एवं एक तालाब ट्यूबवेल से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त सोलर पम्प भी लगाये गये हैं।

(4) एशियाई सिंहो के पुर्नस्थापन हेतु भारत सरकार से बजट की मांग की गई है।

(5) एशियाई सिंहो के पुर्नस्थापन हेतु कूनो अभ्यारण्य के क्षेत्रफल विस्तार हेतु प्रस्ताव भेजे गये है।

(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बनाये गये ''जीरो एक्शन प्लान'' पर सरकार द्वारा प्रतिकिया एवं सुझाव दिये गये है।

5/7/16

(जितेन्द्र अग्रवाल)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग शाखा-2